

भारत 'वशेष वशिषाधिकार' (special privileges) खो देगा: ईरानी राजनयकि

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नई दिल्ली में एक वरिष्ठ ईरानी राजनयकि ने कहा कि यदि भारत सऊदी अरब, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की आपूर्ति के साथ ईरानी क्रूड को बदलने की कोशिश करता है तो ईरान भारत के "वशिष वशिषाधिकार" ("special privileges") को समाप्त कर देगा।

परमुख बदि

- ईरानी राजनयकि ने यह कहा है कि ऊर्जा और कनेक्टिविटी जैसे सामरिक मुद्दों पर जब भी संभव हुआ ईरान ने भारत की मदद की है, लेकिन अभी तक भारत ने चाबहार बंदरगाह में अपने नविश संबंधी वादे पूरे नहीं किये हैं।
- मध्य एशियाई क्षेत्र में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बाजारों तक पहुँच स्थापित करने में सक्षम चाबहार बंदरगाह में भारत के नविश स्तर से ईरान संतुष्ट नहीं है।
- वर्ष 2012 से 2015 के बीच पछिले दौर में अमेरिकी प्रतिबंधों के दौरान ईरान ने भारत को तेल आपूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये पूरी मदद दी थी।
- ईरान का कहना है कि यदि भारत ईरान को अन्य देशों के साथ 10% तेल मांग के लिये प्रतिस्थापित करेगा तो उसे डॉलर-आधारित आयात पर अपनी निर्भरता बढ़ानी पड़ेगी जिससे सीएडी यानी भारत के चालू खाता घाटे में वृद्धि होगी और साथ ही ईरान से प्राप्त अन्य सभी वशिषाधिकारों से भी वंचित होना पड़ेगा।
- दरअसल, ईरान की इस प्रतिरिया का मुख्य कारण ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत को दी गई वह सलाह है, जिसमें कहा गया है कि भारत को ईरान से कच्चे तेल की आपूर्ति में कटौती करनी चाहिये।
- हालाँकि, ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि ईरान भारतीय आवश्यकताओं जैसे- पेट्रोलियम, यूरिया और एलएनजी के लिये एक खुला बाजार बना रहा है और ईरान, भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को भी समझता है।
- संयुक्त व्यापक योजना (जेसीपीओए) या ईरान के परमाणु समझौते से अमेरिकी वापसी के वशिष में ईरानी अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका दुनिया पर एकतरफा भारी लागत लगा रहा है।
- उन्होंने चेतावनी दी है कि खाड़ी क्षेत्र में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि और संघर्ष बढ़ेगा तो यह भारत और चीन जैसे बढ़ती शक्तियों को भी प्रभावित करेगा।
- इसके अलावा ईरान ने उम्मीद जताई है कि भारत चाबहार बंदरगाह में किया गया सहयोग और विकास वास्तव में सामरिक प्रकृति का है, तो भारत इस संबंध में तत्काल आवश्यक कदम उठाएगा।